

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 28 फरवरी, 1984

सं. श्र.वि./जी. जी. एन./116-83/8480.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्जन एस०के० वैल्वेट्स (प्रा०) लि०, 11, इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, गुडगांव, के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई श्रौद्धोगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, श्रौद्धोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ध) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-के अधीन गठित श्रौद्धोगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला (मामले) है/हैं, अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला (मामले) है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या सन्तोषी देवी की पिछले बेतन सहित पुनः नोकरी पर बहाली की जाए ? यदि हां, तो किस विवरण में ?
2. क्या श्रमिकों को नियुक्ति पत्र तथा स्थाई पत्र दिये जायें ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

मुनीश गुप्ता,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग ।

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 28 फरवरी, 1984

सं० श्र.वि./सोनीपत/215-83/8381.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० सी. काम लैबोरेट्रीज प्रा० लि०, 17वां माईल स्टोन जी. टी. रोड, कुण्डली, (सोनीपत), के श्रमिक श्री पूर्ण सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रौद्धोगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, श्रौद्धोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864-ए.एस.ओ. (ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री पूर्ण सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं.श्र.वि./आई.डी./एफ.डी./144-83/8388.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मै. कोन्टीनेन्टल रिफरेक्ट्रीज प्रा० लि०, प्लांट न० 42, सेक्टर 25, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री रियाजुदीन तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई श्रौद्धोगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, श्रौद्धोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ध) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7(क) के अधीन श्रौद्धोगिक

अधिकरण, हरियाणा फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री रियाजुदीन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ग्रो.वि./एफ.डी./10-84/8395.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मैं ज्योति इन्हीनियरिंग वर्क्स मोहना रोड, बल्लबगढ़ के श्रमिक श्री नन्नू खां तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई श्रोतोंगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7(क) के अधीन श्रीद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री नन्नू खां की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ग्रो.वि./ग्राइ.डी./एफ.डी./11-84/8402.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मैं प्राइमरी को-आप्रेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक लिं. हथीन, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री साहज मुहम्मद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई श्रीद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7(क) के अधीन श्रीद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री साहज मुहम्मद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ग्रो.वि./एफ.डी./17-84/8409.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मैंसर्जं शील पैकिजिंग इंडस्ट्रीज, प्लाट नं. 31, सेक्टर 25, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री बिन्देश्वरी शुक्ला तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई श्रीद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7(क) के अधीन श्रीद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री बिन्देश्वरी शुक्ला की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ग्रो.वि./एफ.डी./13-84/8416.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मैं कार्यकारी अभियन्ता हरियाणा अर्बन डैलैपमेंट अथोर्टी डिविजन नं. III, सेक्टर 12, सेक्टर 9, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री यामीन तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के संबंध में कोई श्रीद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7(क) के अधीन श्रीद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री यामीन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?